तक) के दौरान आवंटित किए गए स्टालों/ट्रालियों की क्षेत्रवार संख्या इस प्रकार है:—

रेल	स्टालों की संख्या	ट्रालियां
मध्य	13	1
पूर्व	1	—
उत्तर	13	7
पूर्वोत्तर	20	—
पूर्वोत्तर सीमा	4	—
दक्षिण	17	—
दक्षिण मध्य	1	—
दक्षिण पूर्व	2	—
पश्चिम	36	14

(ख) और (ग) कुछ छद्म नाम वाली शिकायतें प्राप्त हुई थीं जो सिद्ध नहीं हो सकीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Proposal to double the Sharmir-Mangalore rail line

1796. SHRI JOY NADUKKARA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to double the Sharmir-Mangalore rail line;

(b) if so, whether there is any proposal to entrust the work to Konkan Railway Corporation; and

(c) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SURESH KALMADI): (a) to (c) It has been decided to take up doubling of Kuttipuram-Calicut-Mangalore line alongwith construction of a new BG rail link between Guruvayoor and Kuttipuram under BOLT (Build, Own, Lease and Transfer) Scheme in which Konkan Railway Corporation can also participate. On completion of these works, it will serve the purpose of doubling between Shoranur and Mangalore via Trichur.

Vacant posts of judges in Orissa

1797. SHRI SARADA MOHANTY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large number of posts of judges are falling vacant in Orissa high court;

(b) if so, the vacancy position as on 30th October, 1995;

(c) whether steps have been taken by Government to fill up the vacancies; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H.R. BHARDWAJ): (a) to (d) As on 30.10.1995, 8 posts of permanent/ Additional Judges were vacant in the Orissa High Court against the approved strength of 16 permanent/Additional Judges. The appointment of Judges of the High Court is a continuous process. The process of consultation among the concerned constitutional authorities for filling of the existing vacancies in the Orissa High Court is on.

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई सिविल सेवा परीक्षाएं

1798. **प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जा रही सिविल सेवा परीक्षाओं में भारतीय भाषाओं के माध्यम से वर्ष 1990 से 1994 तक वर्ष-वार कितने प्रतिशत विद्यार्थी सफल हुए; और

(ख) संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा वर्ष 1990—1994 से आयोजित की जा रही परीक्षाओं में भारतीय भाषाओं को माध्यम के रूप में चुनने वाले उम्मीदवारों को कितने प्रतिशत सीटें मिलीं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा): (क) और

(ख) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संबंध में अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है:—

वर्ष	उम्मीदवारों का प्रतिशत	
	सिविल सेवा परीक्षाएं	कुल परीक्षाएं*
1990	7.87	8.38
1991	6.54	6.46
1992	12.08	11.14
1993	8.74	8.36
1994	11.80	उपलब्ध नहीं

राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में सूचना केन्द्रीकृत रूप से मॉनीटर नहीं की जाती।

*इस कॉलम में दिए गए आँकड़े उन परीक्षाओं के संबंध में हैं जिनमें भारतीय भाषाएं विकल्प के रूप में उपलब्ध हैं।

राजस्थान में सौर ऊर्जा संयंत्र

1799. **श्री सुन्दर सिंह भंडारी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान के जैसलमेर-बाड़मेर जिलों में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करने के लिए योजना तैयार कर ली गई है; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन): (क) राजस्थान सरकार ने जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में और जोधपुर जिले के कुछ भागों में 300 मेवा० समग्र क्षमता की सौर विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए तीन आशय पत्र जारी किए है। ये आशय पत्र उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी आमंत्रण के माध्यम से आदेश प्राप्त होने के प्रत्युत्तर में जारी किए गए।

(ख) भारत सरकार सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए परियोजनाओं को शुरू करने हेतु राज्य सरकारों को प्रोत्साहित कर रही है। केन्द्र सरकार द्वारा 100% संवर्द्धित ह्रास, पांच वर्ष का कर अवकाश, उदार शर्तों पर ऋण, उत्पाद शुल्क से मुक्ति और रियायती सीमा शुल्क जैसे संवर्द्धनात्मक और राजकोषीय प्रोत्साहन इन परियोजनाओं के लिए उपलब्ध हैं।

Marketing of SSI items by MNCs

1800. SHRI MOHAMMED AFZAL alias MEEM AFZAL: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have taken a decision to grant permission to some multinational companies to make agreements with Indian Companies for marketing the items reserved for small scale sectors, from 1st January, 1993 to 30th June, 1995;

(b) if so, the names and country of these companies;

(c) the fields in which permission has been granted to them to sign agreements with Indian Companies?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): (a) to (b) Yes, Sir. Details of the approvals granted to multinational companies to enter into agreement with Indian Companies for marketing of items reserved for small scale sector during the period from 1st January, 1993 to 30th June, 1995 are given in the enclosed statement.